International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 3, March 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

वैश्वीकरण के प्रभाव तथा चुनौतियां

ऋषि प्रताप सिंह
असि0 प्रो0 राजनीतिशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय
मानिकपुर (चित्रकूट)

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही आविष्कारों एवं खोजों ने मानव विकास की दशा और दिशा को सदैव निर्धारित किया है। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में वैश्वीकरण शब्द काफी लोकप्रिय हो गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी प्रवृत्तियां सम्मिलित है। भूमण्डलीकरण एक परिघटना न होकर एक प्रक्रिया है, जो क्रमशः एक चरणबद्ध तरीके से वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने का प्रयास कर रही है। यह विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं एवं समाजों के मध्य पारस्परिक निर्भरता, अन्तसम्बद्धता और एकीकरण में ऐसे स्तर तक वृद्धि करने की प्रक्रिया है जो विश्व के किसी एक हिस्से में घटित कोई घटना विश्व के अन्य हिस्सों के व्यक्ति को प्रभावित करने लगे। ऐंथनी गिडिंस के अनुसार यह आधुनिकीकरण का परिणाम है। वहीं रोजेनाऊ के अनुसार –भूमण्डलीकरण तकनीकी विकास का परिणाम है क्योंकि वर्तमान कम्प्यूटर क्रान्ति के युग में संचार साधनों को तीव्र विकास हुआ तथा परिवहन की लागत निरन्तर कम हो रही है। वॉर्लस्टीन इसे पूँजीवाद की देन मानते हैं।

वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यधिक व्यापक होता है। सकारात्मक दृष्टि से वैश्वीकरण व्यापार एवं वाणिज्य का इंजन माना जाता है जो विकासशील देशों में पूंजी और संमृद्धि ला रहा है, उनके जीवन स्तर में सुधार कर रहा है। इस विचार के अनुसार यह आर्थिक समृद्धि ही सामाजिक समृद्धि लायेगी। नकारात्मक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का साम्राज्यवाद माना जाता है। यह अविकसित एवं विकासशील देशों में मानवीय अधिकारों का हनन कर रहा है तथा संमृद्धि के नाम पर इनके प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के माध्यम से वैश्वीकरण संस्कृति सहस्वतंत्रता करने का प्रयत्न कर रहा है तथा विकासशील देशों में कृत्रिम आवश्यकताओं का निर्यात करके वहां के स्थानीय समुदायों, पर्यावरण तथा संस्कृति का विनाश कर रहा है। अतः वैश्वीकरण व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि क्या वह उसका समर्थक है या विरोधी, क्योंकि यह प्रत्येक

व्यक्ति को भिन्न–भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। जहां कुछ व्यक्तियों के लिए यह नये अवसर प्रदान करने में सहायक हो सकता है, वही कुछ अन्य के लिए आजीविका की हानि का कारण बन सकता है। इसी वैश्वीकरण के प्रभावों से सम्बन्धित दृष्टिकोण में स्पष्ट विभाजन विद्यमान है।

इस प्रकार कुछ विद्वानों का मानना है कि एक बेहतर विश्व के निर्माण हेतु यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जबकि कुछ अन्य विद्वान वैश्वीकरण के विभिन्न वर्गों पर पडने वाले भिन्न–भिन्न प्रभावों को भयावह मानते हैं। वे तर्क देते है कि इससे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के कुछ व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं जबकि पहले से ही अपवर्जित एक बडे वर्ग की स्थिति और अधिक दयनीय हो सकती है। तथापि अधिकतर लेखकों का मत है कि विश्व की वर्तमान चुनौतियां और समस्याऐं ऐसी है जो पराराष्ट्रीय है तथा जिनके लिये वैश्वीकरण स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। अतः वैश्वीकरण एक बहुआयामी और बहुपक्षीय प्रक्रिया है और जिससे इसके प्रभाव भी भिन्न–भिन्न है।

वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो आधुनिक राज्य के व्यक्तित्व में ही बदलाव ला रहा है वह है वैश्विक आर्थिक प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत व्यापार, उत्पादन तथा वित्तीय लेन–देन का संचालन तीव्र गति से बढती बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है, जो वित्तीय बाजार द्वारा संपादित होता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा अभूतपूर्व स्तर तक बढ गयी है। यह वृद्धि अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा क्षेत्रों के बीच व्यापार दोनों स्तरों पर है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव बहुराष्ट्रीय तथा पराराष्ट्रीय निगमों की मात्रा में वृद्धि है ये कम्पनियां राष्ट्रीय सरकारों की सूक्ष्य आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है ये अपने व्यवसायों को उन देशों में स्थान्तरण कर सकती है, जहां उत्पादन लागत कम है। विशेष रूप से इन कम्पनियों में समन्वित उत्पादन का अन्तराष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अन्तर्गत एक कम्पनी विभिन्न देशों के माध्यम से अपने व्यवसाय एवं व्यापार करती है।

वैश्वीकरण के चलते राजनीतिक शक्ति के प्रभावी केन्द्र केवल आज राष्ट्रीय सरकारें नहीं है। आज वास्तविक शक्ति राष्ट्रीय स्थानीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कई सस्थाओं तथा अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा समझौते तथा लेन–देन के अधार पर मिल बांटकर प्रयुक्त की जा रही है। हालांकि औपचारिक रूप से राष्ट्र राज्य अभी भी प्रभुसत्ताधारी है, परन्तु इसके साथ साथ कई अन्तराष्ट्रीय तथा गैरसरकारी और कानूनी एवं संस्थागत ढाचे का विकास हो गया है जो राज्य में अन्य सार्वभौमिक शक्ति को चुनौती दे रहे है राज्य औपचारिक सत्ता तथा राज्य के वास्तविक व्यवहार ढाचों एवं क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर

आर्थिक व्यवस्था में पृथकता बढती जा रही है इसके साथ ही वैश्वीकरण ने राज्य केन्द्रित रक्षा एवं सुरक्षा नीति की अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था को भी प्रभावित किया है राज्यों के बीच बढते तकनीकी सम्बन्धों ने राष्ट्रीय सुरक्षा तथा इससे सम्बन्धित अस्त्र–शस्त्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को जबरदस्त चुनौती दी है। आज विश्व के कई अन्य बलों का निर्माण किसी एक देश में न होकर विभिन्न देशों में होता है। सैनिक टेक्नोलॉजी यह भी आज वैश्वीकरण हो गया है। इसी तरह जन विनाश के हथियारों के प्रयास ने सभी देशों में असुरक्षा की भावना जता दी है।

वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप कई अन्तरसरकारी संगठनों, अन्तराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों तथा पराराष्ट्रीय दबाव समूहों तथा नेटवर्क का तेजी से विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिशासनों में भी काफी वृद्धि देखने को मिलती है जो राष्ट्र के पारिस्थितिक संदर्भ में ही परिवर्तन कर रहे है। विश्व स्तर पर कानून एवं नियम निर्माण के कई नये केन्द्र भी स्थापित हो गये हैं। जिन्होंने कानून प्रक्रिया को विकेन्द्रीकरण कर दिया है। इसके साथ अर्न्राष्ट्रीय कानून में परिवर्तन ने व्यक्तियों, राष्ट्रीय सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों को नये अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अन्तर्गत खड़ा किया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्र राज्यों की शक्ति तथा सीमाओं को मान्यता देता है। उसके अधिकार एवं कर्तव्यों पर भी बल देता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में आज राज्य की निरंकुश सत्ता पर कई प्रकार की सीमाऐं लगी हुई हैं जैसे 150 से अधिक राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप आज एक ऐसे राष्ट्रराज्य का मिलना मुश्किल है, जो अपनी निश्चित सीमाओं के अन्दर स्वतंत्र हो तथा वह बाहरी संस्कृति प्रभावों से परे अपनी अलग राष्ट्रीय अस्मिता को संरक्षित कर सके। आज राज्यों में रहने वाले नागरिकों को सामाजिक दृष्टिकोण तथा मूल्यों का निर्माण राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान के सन्दर्भ में हो रहा है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के वे परिणाम नहीं निकले है जैसा कि भविष्यवाणी की गयी थी इसने गरीब देशों मजदूर वर्ग तथा पर्यावरण की परवाह नहीं की। यह पूंजीवादी बाजारीकरण व्यवस्था तथा मुक्त व्यापार की वकालत करता है। यह विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों को शरण इस शर्त पर देती है कि वह अपने यहां ढांचागत समायोजन की प्रक्रिया का पालन करे तथा शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर कम खर्च करें, उद्योगों का निजीकरण उत्पादन को निर्यातोन्मुखी विदेशी पूंजी निवेश की आज्ञा देनी होगी। जिससे धन एवं शक्ति कुछ हांथों में केन्द्रित हो जाता है, और आम जनता पहले से अधिक गरीब हो जाती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमेशा इस फिराक में रहती हैं जहां मुनाफा बढ सके और वहां की

सरकारें श्रम अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी करें। वास्तव में वैश्वीकरण के चलते हर वस्तु बिकाउ हो गयी है। इसके चलते अमीर और गरीब देशो में अन्तर बढता जा रहा है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र एवं समाज में निम्नतम वर्ग की रचना हो रही है। यदि वैश्वीकरण के अनुसार राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना तो सपोषित विकास की धारण को जबरदस्त धक्का पहुंचता है। जैसा कि नोवल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टीजलिरज ने अपनी पुस्तक 'मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क' में वैश्वीकरण की आलोचना की है उनके अनुसार 1. इसके नियम अनुचित है, ये गरीब देशों को और गरीब कर रहा है। 2. इनमें भौतिक मूल्यों को बाकी सभी मूल्यों (पर्यावरण समेत) से अधिक वरीयता दी जा रही है। 3. वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीय प्रजातन्त्र की धारणाओं में कमी की है। 4. वैश्वीकरण से सभी को लाभ नहीं हुआ। विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों में हानि उठाने वाले समूह भी काफी है। 5. विकासशील देशों पर आर्थिक व्यवस्थाऐं बाहर से आरोपित की जा रही हैं। इससे आर्थिक नीति तथा संस्कृति का अमेरिकाकरण होता जा रहा है। इसलिए वैश्विक न्याय का प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है। वैश्वीकरण की सबसे बड़ी चुनौती नैतिक है। अर्थात् क्या पश्चिम के समृद्ध देशों को अविकसित और विकासशील देशों के उपेक्षित वर्गों परम्पराओं एवं सस्कृतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए या इन्हें केवल इनके प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के दोहन तक सीमित रहना चाहिए। अतः वैश्विक न्याय की धारणा भूमण्डलीकरण के सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती है क्योंकि वैश्वीकरण का अभिप्राय सामाजिक सम्बन्धों में गुणात्मक वृद्धि तथा प्रसार है। मानव जीवन के कई क्षेत्रों में अब राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय का अन्तर धुंधला पड़ता जा रहा है। विश्व स्तर पर न्याय तथा प्रजातंत्र की कमी राष्ट्रीय स्तर पर इनकी उपलब्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। जैसा कि अर्मत्यसेन का कहना है कि वैश्वीकरण के लाभ और हानियों पर चिन्तन करते हुए न्याय की आवश्यकता के बारे में सोचना अनिवार्य है। चूंकि न्याय का मूल आधार है – उचित एवं निष्पक्ष वितरण। अतः वैश्वीकरण के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण सवाल है – क्या वैश्वीकरण के लाभों का वितरण उचित हुआ है अथवा हो रहा है ? वास्तव में वैश्वीकरण के सन्दर्भ में एक संशोधित वैश्विक व्यवस्था का प्रयत्न उचित न्याय तथा अवसरों का उचित वितरण होना चाहिए।

परन्तु इसमें जो सबसे महत्वूपर्ण तत्व जोड़ना आवश्यक है वह है सामाजिक सुरक्षा। बाजार अर्थव्यवस्था में संशोधन और सामाजिक सुरक्षा दोनों मिलकर असमानता तथा गरीबी के वर्तमान स्तरों में काफी कमी ला सकते है।

इसलिए टॉड सलोन का विचार है कि आवश्यकता वैश्वीकरण को समाप्त करने की नहीं है बल्कि वैश्वीकरण को नीचे से आरम्भ करने की है। इसके साथ ही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती इस वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा बाजार के लाभों को इस प्रकार से बचावर रखना है जिससे समुदाय पर्यावरण तथा मानवीय संसाधनों को भी नुकसान न हो। यह अन्योन्याश्रित के प्रत्येक स्तर मानवीय अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के उन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने हो सकता है जो सामूहिक तथा व्यक्तिगत कल्याण को प्रभावित करते है। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रीय संगठनों, सामुदायिक संगठनों तथा नागरिकों सभी को भागेदारी के इस नये नेटवर्क के साथ जुड़ने की आवश्यकता है ताकि विश्व के वंचित समूहों की भौतिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ किया जा सके।

इस प्रकार वैश्वीकरण की समग्रता से विश्लेषण करने पर इसे सर्वसमावेशी बनाये जाने की जरूरत बताई गयी है। साथ ही वैश्विक आर्थिक संस्थाओं के संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधार के द्वारा सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक भावना एवं कार्य पद्धति के द्वारा सामाजिक न्याय तथा वैश्विक न्याय का पथ अग्रसित होगा। समाज के वंचित, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित वर्ग विकास की मुख्य धारा, ढाचे तथा वैश्वीकरण की संकल्पना सार्थक तथा प्रासंगिक होगी। अतः मानवीय प्रगति की निरंन्तर मात्रा गुणवत्तापूर्ण, गरिमामय, समतामूलक, समावेशी तथा सम्पोषित मूल्यों एवं लक्ष्यों की ओर अग्रसर है।

संदर्भित पुस्तकें :–

1. आर0सी0 वरमानी – समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (गीतांजलि पहली शिवा हाउस 2007) नई दिल्ली।
2. सुनील गुप्ता एवं कमल कुमार सिंह – सुशासन (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत) 2016
3. बी0 एल0 घडिया – समकालीन राजनीतिक मुद्दे (साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा) 2016
4. जॉन वेलिस, स्टीव स्मिथ – ग्लोबलाइजेशन आफ वर्ल्ड पालिटिक्स (2015)
5. पत्रिकाऐं – वर्ल्ड फोकस, इण्डिया टुडे, समाचार पत्र।